

17.36 hrs

**APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL\***

MR. SPEAKER : The House will now take up Appropriation (Vote on Account) Bill.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services, of a part of the financial year 1984-85.

MR. SPEAKER : The question is : "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1984-85."

*The motion was adopted*

MR. SPEAKER : The Minister may now introduce the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I introduce the Bill.

I beg to move :—

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1984-85, be taken into consideration."

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1984-85, be taken into consideration."

श्री रामबतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, प्रगर आपकी इजाजत हो, तो मैं बैठ कर अपनी बात कहूँ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : प्रगर आपकी इजाजत हो, तो वह अपने भाषण को सदन की मेज पर रख दे।

श्री रामबतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मैं इस विषय पर वृहत् क्रम में निम्न चार बातों का उल्लेख करते हुए मंत्री महाशय से स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा रखता हूँ।

देश के 1 लाख 27 हजार स्वतंत्रता-सेनानियों की स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन मिल रही है। सन् 1980 के अगस्त में प्रत्येक सेनानी को 300 रुपए माहवारी पेंशन की राशि मिल रही है। उनकी विधवाओं को 200 रुपए माहवारी मिलते हैं। सन् 1980 अगस्त से पूर्व उक्त क्रम, 200 और 100 रुपए माहवारी मिलते थे।

सन् 1980 की जुलना में प्राज्ञ महशय कई सुना चढ़ गई है, जिनका सुनन केन्द्राव सरकार के सम्बन्धों की चार किस्तों के महशय मन्त्री का बकाया है। मैं यहाँ सेनानियों की जुलना उनके साथ नहीं करना चाहता। उक्त महशय उन्हें भी छोड़ने की तरह मना रही है। इस लिए मेरा अनुरोध है कि उनकी 300 रुपए की राशि को बढ़ा कर 500 रुपए माहवारी कर दिया जाए, ताकि उन्हें स्वतंत्रता-सेनानी संश्लेषण महशय का नामना करने एवं अपने परिवार के अर्थ पालन में समर्थ हो सके।

पिछले बजट सत्र में इसी प्रकार के विधेयक पर हो रही बहस के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए इसी प्रकार के प्रश्न के जवाब में आपने गृह मन्त्री की राय से कहा

\*Published in Gazette of India Extra Ordinary Part II section-2 dated 14.3.1984

\*\*Introduced/Moved with the recommendation of the President.

का कि सरकार पेशन की राशि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

[Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

17.39 hrs.

मैं जानना चाहूंगा कि आपके डल प्राश्वासन का क्या हुआ।

2. सरकार भूतपूर्व संसद सदस्यों को भी कम से कम तीन सौ और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये माहवारी पेंशन देती है। अर्थाधिक महंगाई को देखते हुए उन्हें मिलने वाली यह राशि भी कम है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि, उन्हें मिलने वाली राशि को बढ़ा कर क्रमशः पांच सौ और सान सौ रुपये माहवारी कर दी जाए।

प्रायः सभी भूतपूर्व संसद राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित हैं। अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों का रेलों से यात्रा करना पड़ती है जिस के क्रम में उन्हें बहुत भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेल यात्रा में सुविधा के लिए प्रत्येक भूतपूर्व संसद को कम से कम एक प्रथम श्रेणी का नाथ पाम दिया जाय। उन के सगठन की ओर से सरकार को ज्ञापन भी दिये जा चुके हैं जिस में उनका बाता का उल्लेख है। कहते हैं कि संसद सदस्यों के वेतन-भत्ता-पेंशन संबंधी संयुक्त समिति उन्हें रेल पाम प्रदान करने की सिफारिश भी कर चुकी है।

3. दिनों दिन महंगाई में बृद्धि के कारण देश के केन्द्रीय सरकार के 36 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की चार किस्तें बकाया पड़ गयी हैं। पांचवीं किस्त भी होने ही वाली है। फिर भी, सरकार बार बार प्राश्वासन देने के बावजूद कान में हई बाल कर बैठी हुई है और कर्मचारियों को प्राश्वासनों के बावजूद महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों की भुगतान नहीं कर रही है।

सरकार की इस कर्मचारी विरोधी नीति से उनमें असंतोष की भाव जल रही है और वे किसी भी दिन आन्दोलन का रास्ता ढकड़ सकते हैं। अतः वित्त मंत्रों से मेरा अनुरोध होगा कि वह कर्मचारियों की बकाया की संपूर्ण राशि का तकद भुगतान करें।

4. 50 लाख भूतपूर्व सैनिकों की गंभीर समस्यायें देश में आज करीब 50 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। प्रत्येक वर्ष 70 हजार जवान और एक हजार अधिकारी सेवा निवृत्त किए जाते हैं। जवान से लेकर नायक तक की सेवा निवृत्ति की आयु 32 से 40 वर्ष है जब कि अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होता।

सेवा निवृत्ति हो जाने के बाद अधिकांश जवान स्वयं की पूरी तरह से असहाय महसूस करते हैं। इनमें से करीब 80 प्रतिशत ग्रामों में रहते हैं और ग्राम तौर पर उनके पाम जीविका का कोई साधन नहीं है। लड़ाई के अनावा हिमी अन्य कार्य में प्राश्रित न हो पाने की वजह से उनके पास जा जमीन होती है उस पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं।

आर्थिक समस्याओं तनावों और असंतोष के कारण उन्हें गलत तरीके के लोगों का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इनमें से आज भारी तादाद में अकाली उपद्रवादियों और असम आन्दोलन के साथ हैं। ब्रिटिश सेना में प्राश्रित भूतपूर्व नागा सैनिक पृथक नागा राज्य की रीढ़ रहे हैं। मिजो नेतृत्व में अधिकांश भूतपूर्व सैनिक ही हैं। मेघालय की मांग विलियम मंत्रमा ने भूतपूर्व सैनिकों के बल पर ही जीती थी। त्रिपुरा उपजाति समिति में बहुत से भूतपूर्व सैनिक हैं। डकैती में भी वे भारी तादाद में शामिल रहे हैं। दिल्ली और आस पास की घटनाओं में भी वे शामिल रहे हैं।

भूतपूर्व जवानों के सही पुनर्वास में सरकार की बिकलता से निराशा ही भूतपूर्व

सैनिक इन सारी गलन गतिविधियों में शामिल है।

भूतपूर्व सैनिकों की इस दर्दनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्डियन एक्स सर्विस लीग ने सरकार से मांग की है कि भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन बोर्ड में संशोधन किया जाय, उन्हें सेवा निवृत्त होने के बाद प्रदत्त सैनिक संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में काम दिया जाय, उनके लिए अलग मंत्रालय गठन किया जाय, यात्रा में रियायत दी जाय, सैनिक और मिलित घम्पनालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाय या उनके लिए विशेष घम्पनालों का निर्माण किया जाय, एक हजार रुपये तक पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को मुक्त शिक्षा दी जाय, रक्षा सेवा बंद खोले जाय आदि। ये उनमें इन मांगों को सर्वथा उचित मानता हूँ।

धन: मंत्री महोदय मैं मेरा प्रनुरोध होगा कि वह मेरी चार्ज वाता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर उठाया गया गयी मांगों को स्वीकार कर विभिन्न प्रकार के लोगों के सम्बन्ध दूर करे।

प्रो अजित कुमार मेहता (ममस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महादय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरिन क्रांति जो बड़ी चर्चा रहनी है, कहा जाता है कि उसकी बड़ी उल्लेख्यता है किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हरिन क्रांति जो भी सफलता है वह असफलता के महासागर में केवल एक द्वीप बनकर ही ही रह गई है क्योंकि हरिन क्रांति कही पर सफल रही है जहाँ की भूमि सिंचित है, अतिचिंत है, भूमि तक हरित क्रांति की सफलता अभी तक नहीं पहुँच पाई

है। आज भी हमारे देश के किसान मानसून की दया पर निर्भर करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हरिन क्रांति से कहीं अधिक जोर घाप ड्राई फार्मिंग के ऊपर दे, उनके लिए नयी टेक्नालाजी विकसित करे ताकि देश में खाद्यान्न की पैदावार बढ़ सके और अभी भी कम से कम पिछले दो साल में जो घाप खाद्यान्न के प्रायान पर निर्भर करते हैं उसका समाप्त किया जा सके तथा इसीलिए देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।

इस प्रकार मैं आपरेशन प्लन की विफलता का चर्चा करने में भी कुछ लोग चौक जाते हैं क्योंकि वे लोग समझते हैं कि आपरेशन प्लन काफी सफल रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इसकी जो उपलब्धता है वह केवल कुछ महंगी नक ही मौजिन है, गहरा न.ग.कों को नले ही घाप कुछ दूधुकी उपलब्धि कर सके ही लेकिन देशान में इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। इस संबंध में मूल्यांकन समित गठित की गई है उसके द्वारा प्लन आपरेशन का गहरा मूल्यांकन होना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि आपरेशन प्लन में लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। उसके पदचाल इस नीति पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

जहाँ तक रक्षा सेवाओं का सम्बन्ध है, हमारे शास्त्री जो ने विशद रूप में इसके बारे में कहा है इसलिए मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह गई है परन्तु इनका मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि रक्षा सेवाओं में गमाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र से भर्ती को जानी चाहिए। यदि रक्षा सेवाओं में किसी एक भाग से या किसी एक वर्ग में ही अधिक भर्ती कर ली जायेगी तो उसका हमारी रक्षा सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

घोर वह सारी व्यवस्था एकतरफा हो जायेगी। इसलिए आवश्यकता है कि हर वर्ग और हर क्षेत्र का रक्षा मेवात्रा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन सम्बन्ध में आप जो भी काइटीरिया निर्धारित करें परन्तु हर क्षेत्र में उममें वर्ग और हर भर्ती हानो चाहिए।

जहाँक शिक्षा का सम्बन्ध है, हमारे देश में आज दोहरी शिक्षा नीति प्रचलित है जिसका परिणाम यह है कि सम्पूर्ण वर्ग कलक के पब्लिक स्कूलों में पढ़कर अफसर बन जाने हैं और जनसाधारण के लड़के लाभान्वित नहीं हो पाते क्योंकि उनके लिए पढाई की दूसरी व्यवस्था है। इसलिए आवश्यक है कि हम दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त किया जाना चाहिए। ये शिक्षा के स्तर को नीचे तान की बात नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में भी आप शिक्षा का स्तर इतना ऊपर करते जिसमें कि दोहरी शिक्षा नीति की आवश्यकता ही न रह जाए। दोहरी शिक्षा नीति जो अभी प्रचलित है उसका समाप्त करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

हाल ही में जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी में नामांकन की जो नीति थी उसको बदल दिया गया है। जिसकी वजह से देश के पिछड़े हुए हिस्सों को जो लाभ मिलता था वे अब उमसे बचिन रह जायेंगे। इसका सबसे बुरा परिणाम यह होगा कि यह मुविषा अलाइट लोगों तक सीमित रह जायेगी। शिक्षा के स्तर को कायम करने के नाम पर ऐसा किया गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमसे पिछड़े इलाके के लोगों को कोई लाभ मिलेगा? वहाँ के लोग कम सख्या में विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। इस प्रकार जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे जो मूल

भावना थी कि शिक्षा को एक ऐसे क्षेत्र तक ले जाया जाएगा जिससे कि पिछड़े हुए लोगों को फायदा मिल सके उस मूल भावना को घाघान होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पूर्व एडमोशन पालिसी थी उसको कायम रखा जाए और नई पालिसी जो अख्तियार की गई है, उसको रद्द किया जाए।

शास्त्री जी अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उससे कभी भी सहमत नहीं होंगे। मेरा कहना यह है कि बिहार में ऐसा कोई कालेज नहीं है जिसको कि हम कह सकें कि वह महीं रूप में काम कर रहा है को और उसको रैप्युटेशन प्राप्त है। जिसको रैप्युटेशन प्राप्त है वह एक ही कालेज है बिरला इंस्टीचूट आफ टेक्नोलॉजी

श्री रामावतार शास्त्री : जहाँ पर कि सबसे ज्यादा गोलमाल है।

श्री अजित कुमार मेहता : ज्यादा गोलमाल 'मस्टर इंस्टीचूट' में है, जिस की बातें आप नहीं करेंगे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल यही एक ऐसा महीं विद्यालय है, जिसके रनानक को राज्य के नगदर और विदेशों में भी मान्यता, रैपुटेशन प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उम विद्यालय के बहुमंख्यक शिक्षक वर्ग और छात्रों का औरसे भी और लोगों की और से भी यह मांग बराबर आ रही है कि उम विद्यालय के स्वायतत्ता के स्तर को बढ़ाकर डीम-टु-वि-युनिवर्सिटी का स्तर दे दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हम पर सम्भोरता पूर्व विचार करें।

बिहार काँग्रेस का बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर एक भी सुपर बर्मल पाबर स्टेशन नहीं है।

जब कि उसके बगल के प्रदेशों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। एक ही जगह पर इतने सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन बना दिए गए हैं, जिसमें कि करीब डेढ़ लाख टन कोयला रोज जलेगा तो इससे उत्पन्न प्रदूषण की घाब कल्पना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन अलग-अलग जगहों पर बनाए जायें। बिहार में कर्णपुरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है या तो दामोदर को ट्रिब्यूटरी हारो नदी से या कोयलाकारी परियोजना के कंचमैट के समर्थनाने से काफी पानी उपलब्ध है और कोयला भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि उनका कर्णपुरा क्षेत्र में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की जाए ताकि बिहार और कुछ अन्य क्षेत्रों की बिजली की समस्या दूर हो सके।

बायोगंस की स्थापना के बारे में सरकार ने बहुत कांशनेम दिखाई है लेकिन क्या उस के लिये उचित प्रबन्ध किया गया है? मैं सुझाव देना हूँ कि बायोगंस और सीर ऊर्जा के लिये आप ऐसा नियम बना दें कि शहरों में सीर ऊर्जा के लिये बड़े बड़े मकानों पर संयंत्र लगाना आवश्यक हो जायें वहाँ पर म्युनिसिपल कारपोरेशन की ओर से सुलभ शौचालय हैं वहाँ बायोगंस प्लांट बँटाने की अनिवार्यता कर दी जायें तो निश्चित रूप से बायोगंस और सीर ऊर्जा के प्रसार में सहायता मिलेगी।

इसके बाद छोटा नागपुर के आदिवासियों के नियोजन की जो समस्या है मैं उसकी ओर आप का ध्यान आकषित करना चाहूँगा। ग्राम जानते हैं वह अपार खनिज सम्पदा का क्षेत्र है इस लिये वहाँ पर बड़ी

बड़ी योजनायें तथा परियोजनायें चालू की जाती हैं और उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि जिन आदिवासियों को बिस्थापित किया जायेगा जिनकी जमीनों को परियोजना के लिये लिया जायेगा, उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उस परियोजना में अवश्य नौकरी दी जायेगी। लेकिन इस प्रावधान का कड़ाई से पालन नहीं होता है। मैं हाल ही का एक उदाहरण आप के सामने रखना हूँ कोल इन्डिया का उस क्षेत्र में नौकरी देने के लिए एक पैनल बनाया गया किन्तु ऐन-मीके पर उस पैनल को कन्सिडर कर दिया गया और यह कहा गया कि इस स्तर की नौकरी के लिये उनका नाम एम्प्लायमेंट एक्विवेन्स में घाना आवश्यक है और चूकि ये नाम एम्प्लायमेंट एक्विवेन्स में नहीं आये है इस लिये पैनल को रद्द किया जाता है। मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान एक पत्र भिज कर पहले ही आकषित कर चुका हूँ, इस लिये मुझे घाना है कि वे निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे। यह हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है जो प्रतिज्ञा आप करने है यह उसका हल है, इस तरह से आपकी बिटबमनीयता समाप्त हो जायेगी और परियोजनाओं के लागू करने तथा उनका कार्यान्वित करने में बहुत बाधाये घायेंगी। इस लिये इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

18.00 hrs

मेरा खान्तिम मुद्दा यह है कि योजना आयोग का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि राज्यों का उममें उचित प्रतिनिधित्व हो। मेरे राज्यों का जो आप के खोत है वे योजना आयोग के अधिकार में हैं लेकिन इस में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, वह नाग्य है। आप केवल एक पीठ

मिनिस्टर को बुला लेते हैं लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं है। घाय उनका बान ही केवल सुन लेते हैं। (इम्बबवान) घायको क्या फायदा मिलता है बीच में इनटररेक्ट करने से। कितना ज्यादा घाय इनटररेक्ट करेंगे, उनका अधिक समय मैं लूंगा और जो मैं बोलना चाहता हूँ वह बोल कर ही रहूंगा।

मेरा कहना यह है कि योजना आयोग का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व उसमें हो। इसमें यह फायदा होगा कि राज्यों में जो विद्रोह का प्रवृत्ति पैदा होती है वह समाप्त जाएगी। हर राज्य के लोग यही समझते हैं कि घाय के साथ सैनिकों ने अपने हाथों में रख लिये हैं और उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है और अपने राज्य में होने वाली घाय को भी वे उचित ढंग में रख नहीं कर सकते इसमें स्थायित्व की मांग होती है और देश के बिखराव की स्थिति पैदा होनी है। इस लिए मेरा मुझाव यह है कि योजना आयोग का गठन इस तरह से किया जाए जिसमें राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व हो। राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व होने से योजना आयोग के निर्णय किसी एक तरफ नहीं झुकेंगे और किसी राज्य के प्रति बैरवाद नहीं होगा।

इन्हीं मसलों के साथ मैं घाय को बच्यवाद देना हूँ कि घायने मुझे बोलने का समय दिया और मन्त्री महोदय से घायह करता हूँ कि जिन मुद्दों को मैंने उठाया है, उनमें जिनका वे जवाब दे सकते हैं उनका जवाब दें।

**SHRI PRANAB MUKHERJEE :** Mr Ramavatar Shastri has raised four points and prof. Ajit Kumar Mohta has raised a number of points, As you know Sir the practice with regard to the points which are not directly related to my Ministry is that normally we pass on the suggestions and points to the respective Ministries,

**SHRI RAMAVATAR SHASTRI :** Most of my points related to your Ministry,

**SHRI PRANAB MUKHERJEE :** About raising the Pension of the freedom fighters, the hon. Member himself is aware that it is under the active consideration of the Ministry of Home Affairs.

**SHRI RAMAVATAR SHASTRI :** For how long? Last Year also You had said the same thing. How long will it take ?

**SHRI PRANAB MUKHERJEE :** If I had something in my pocket I would have done much earlier. We are taking note of it. Similarly, this problem has also come to our notice, that is, facilities to ex-Members. As You know, we have recently done something for the present Members. So I will take some more time to absorb the shock of what we have done for the present Members and thereafter I will do something for the ex-Members.

**AN HON. MEMBER :** By then we will have become ex-Members.

**SHRI PRANAB MUKHERJEE :** You will agree that we have given a substantial increase so far as the present Members are concerned.

**AN HON. MEMBER :** Many of us will become ex-Members.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** You will be elected again and you will come back.

**SHRI PRANAB MUKHERJEE :** Regarding ex-servicemen, one problem we have about pensioners. The other day my colleague, the Defence Minister has suggested this. The problem particu-

larly, so far as pension is concerned, is about computation. We have offered to them the ready-reckoner. If they want to have the ready-reckoner, their claims will be settled immediately and about those who will not accept it, point-to-point fixation in respect of those cases will be done. One can understand the problem when eleven lakhs of people are involved and covering services over a period of years, 15 to 25 years ..

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Finance Minister, there is not much of difference also. As a pensioner, I have studied and I have also taken the arrear. The ready-reckoner is all right. There is a difference of only one or two rupees.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : That is why I have suggested. In fact, the Defence Minister the other day discussed in detail on the floor of the other House.

About bank loans you have discussed in detail with my colleague, Mr. Janardhana Poojary.

Regarding DA instalments I have got some provisions in the Budget but I will not be able to make any commitment right now...

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : What is the use of keeping it ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, these are the common points they have made. But only a couple of observations I can make. These are the exercises we are making. These are the general points. Whether Operation Flood has become successful or not and whether the Green Revolution has become successful or not—you will get ample opportunity to bring them to the attention of the Ministers when the respective demands come up. Only one point I would like to clarify when he referred to the Planning Commission and ascertaining the views of Chief Ministers.

So far as the National Development Council is concerned, Chief Ministers

come by their right—it is not an advisory ... *(Interruptions)* The Planning Commission formulates the Plans but the ultimate approval of the Plan rests with NDC. And NDC consists of all the Chief Ministers .. *(Interruptions)* No, no. I totally disagree with you, because I myself conducted a number of conferences of Chief Ministers. They express their views. The recent meeting I had was on Sales Tax. Another meeting I am going to have on the 24th. They do not want to bulldoze the majority view and we do not want to suppress the views of the other. We try to work out a consensus and to my mind this system has proved to be successful. We should rather strengthen this system instead of just institutionalising and formalising it.

All other points and suggestions of the hon Members I will pass on to the respective Ministers.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the motion for consideration to the vote of the House.  
The question is :

“That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1984-85 be taken into consideration.”

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the question is :

“That clauses 2 to 4 and the Schedule stand part of the Bill.”

*The motion was adopted*

*Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill*

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, I beg to move :

“That the Bill be passed.”

MR DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : what is the Bill, sir ? .. Misappropriation Bill ?

MR DEPUTY SPEAKER : Hon Members, before I call the Minister of Energy to make his statement, the Parliamentary Affairs Minister made a request to the Chair that since they are going to declare holiday on Friday, we may take up the Supplementary Demands also I have consulted Mr. Satyasadhan Chakraborty and Mr. Ram Vilas Paswan who are the valiant Opposition Leaders that we will pass it to-day and they have also agreed. *(Interruptions)* We have to take the views of the Opposition *(Interruptions)* Therefore, after this statement we are going to take up the Supplementary Demands also.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI [Patna] : Our speaker is not here. How can you take it up ? We protest.

MR DEPUTY-SPEAKER : Is it the sense of the House that we take up the Supplementary Demands also ?

SEVERAL HON MEMBERS : Yes, yes

THE MINISTER OF ENERGY SHRI P. SHIV SHANKAR) Why don't you tell him that he is also a valiant opposition leader so that he will sit down ?

PROF AJIT KUMAR Mehta (Samastipur) : No advance notice or information was given.

MR DEPUTY-SPEAKER : Please listen...

PROF AJIT KUMAR MEHTA : I can go to any extent to help you and cooperate with you.

MR DEPUTY-SPEAKER : Please listen to me. We have asked for a holiday on Friday because of Holi. That is what I am telling. The sense of the House is that we pass the supplementary Demands also.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I am walking out in protest.

18-10 hrs

*Shri Ramavatar Shastri then left the House*

MR DEPUTY SPEAKER : I am sorry. We cannot satisfy everybody.

Now, the Hon. Minister of Energy may make his statement.

Shri P. Shiv Shankar.

18.11 hrs

#### STATEMENT ON "NEW GAS STRIKE IN GODAVARI ONSHORE AND OIL & GAS STRIKE AT GANDHAR IN CAMBAY BASIN"

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. SHIV SHANKAR) : Sir, I am glad to announce two important discoveries which have been made in the last four days in Krishna-Godavari basin and in the Cambay basin.

On March 10, 1984, gas with condensate was struck at Well Bhimonopalli-1 located about 60 kms. South-East of Rajamundhari in East Godavari district. The first object tested in intervals of 2810.5 metres to 2813.5 metres gave a gas flow at a rate ranging from 27000 to 40000 cubic metres per day with the choke size varying from  $\frac{1}{4}$ " to  $\frac{1}{2}$ ". Seven more objects in this well are yet to be tested.

This is the fourth well drilled in the onland Godavari basin, the earlier wells being one at Razole and two at Narsapur. Wells both at Razole and Narsapur had earlier given indications of the presence of gas. An adjacent well at Amlapuram which is under drilling will also be tested shortly.

Drilling operations are planned at five more locations in Godavari